(MIJ) 2015, Vol No 1, Jan-Dec **e-ISSN: 2454-924X; p-ISSN: 2454-8103**

THE IMPACT OF REGIONAL DISPARITIES IN THE DEVELOPMENT OF THE INDIAN ECONOMY

Dr Seema Yadav
Asst Professor, HOD, Department of Law, Sri Varshney College, Aligarh

भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में क्षेत्रीय विषमताओं का प्रभावः संक्षिप्त अवलोकन

डा.सीमा यादव
असि. प्रोफेसर, विभागाध्यक्षा, विधि विभाग श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ

आर्थिक क्षेत्रीय विषमता असमानता का तात्पर्य है कि देश के विभिन्न राज्यों के आर्थिक तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर में पाई जाने वाली भिन्नता । नि:सन्देह अर्थव्यवस्था का अप्रत्याशित अवसाद जो ***1930*** की भीषण मंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को झेलना पड़ा उससे उबरने में कई वर्ष लग गई इसी तरह वर्ष ***2007*** अमेरिका के वित्तीय प्रबंधन बाजार में आई मंदी ने ***2007*** वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया भारत भी इससे अछूता नहीं बचा इसका प्रभाव अध्यक्षता वर्ष ***2008*** के अंतिम चतुर्थेश: में महसूस हुआ तथा वर्तमान में भारतीय समाज इसके दुष्प्रभाव के गर्त से उबरने की अपेक्षा झुलस कर रह गया है आपसी प्रतिस्पर्धा, वैमनस्यता, विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति भ्रष्टाचार आदि की अप्रत्याशित वृद्धि के साथ भारतीय अर्थ.व्यवस्था पर क्षेत्रीय बिषमताओ की अभिवृद्धि का दुष्प्रभाव अपने चरम पर है।

अर्थव्यवस्था : सामान्य भाषा में इंग्लिश शब्द 'इकोनामी' मितव्यता का संकेत देता है वर्तमान संदर्भ में इसे अपने विस्तृत रूप में लिया गया है जिसका अभिप्राय मौद्रिक प्रबंधन है।वर्तमान युग अर्थ प्रधान है तथा "अर्थस्य पुरुषों" दास की कहावत "स् सर्वोगुण वाचनम् ... " आजकल बहुतायत से व्यवहारिकता में अपनाई जा रही है।सं स्कृत लोकोक्ति मे चार पुरूषार्थ बताये गए है जिसके द्वारा मानवीय जीवन की सार्थकता को समझा जा सकता है:.

"धर्मार्थ काम मोक्षणाम् यश्चे कोअपि न विधते।
अजगालस्य स्थनैव तस्य जन्म निरर्थकम्।।

यहाॅ धर्म का संबंध किसी धर्म विशेष से न होकर उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं तो आज शब्द उन वित्तीय संसाधनों का संकेत देता है जिससे न केवल जीवित रहा जा सकता है कल के अच्छी प्रकार जीवन जिया जा सकता है मुद्रा कृष्ण की सामान्य अवस्था मुद्रा स्फीति क्या सुकून चैन के बीच की स्थिति सॉग अर्थव्यवस्था कही जा सकती है पर मुद्रास्फीति और इस स्थिति में कमीशन मुद्रा की क्रय शक्ति घटती बढ़ती रहती है जब उत्पाद आवश्यकता से बढ़ जाता है तो अवसाद की स्थिति आ जाती है और मुद्रा की क्रय

(MIJ) 2015, Vol No 1, Jan-Dec **e-ISSN: 2454-924X; p-ISSN: 2454-8103**

शक्ति बढ़ जाती है परंतु इसके विपरीत स्थिति होते ही वह की जाती है आ जाता है अमेरिका में आई मंदी का सर्वाधिक प्रभाव और हजारों की संख्या में कर्मचारियों की अनेक लोग बेरोजगार हो गए और स्वदेश लौटने लगे। बेरोजगारी का आंकड़ा भारत में बढ़ने लगा जिस प्रकार अमेरिकी मंदी का कुप्रभाव भारत पर भी पड़ा विदेशी मुद्रा जो वेतन आदि के रूप में भारत को मिली थी घटने लगी शेयर बाजार के निवेश विपरीत रूप से प्रभावित होने लगे। विदेशी व्यापार की स्थिति डामाडोल होने लगी ब्रेन ड्रेन की गति तो प्रतिवर्ती होने लगी परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मिल गई बेरोजगारों के साथ सफेदपोश अपराधों की बाढ़ आ गई लूटपाट की घटना बेशुमार बढ़ने लगी जिससे शासन प्रशासन आजतक रोक नहीं पा रहा है।

भारतीय समाज की संरचना एवं क्षेत्रीय विषमता है: भारत में भावनात्मक रूप में विविधता में एकता की बात कही जाती है परंतु क्षेत्रीय विषमताओं उस एकता को छिन्न.भिन्न करती लगती हैं यथा उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग रहा उत्तराखंड देशी . पहाड़ी के अंतर को इतना बढ़ाता रहा किअलग राज्य बन गया । उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आधार वहां की मातृशक्ति है यदि यदि मातृशक्ति निष्क्रिय हो जाए तो पुरुषों को रोटी के लाले पड़ सकते हैं बच्चों की देखरेख से लेकर जानवरों के लिए चार भोजन के लिए धन की व्यवस्था और घर के समस्त कार्यो को करना वहा की महिलाओं की वविवशता है क्योकि पुरुष नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर भी कृषि कार्य महिलाओं से ही कराते हैं तथा स्वयं ताश खेलना, दारू पी पत्नि को आयेदिन प्रताड़ित करना,पेंशन के रूपये शराबखोरी एवं सुल्फे मे खर्च करना आदि प्रथागत सामाजिक नीति का हिस्सा हो, यहाॅ तक कि नाराज पति अपनी पत्नी को आसानी से छोड़ सकता है वहां की प्रथागत कानून के अनुसार ₹*2* के स्टांप पेपर पर 'ला दावा' लिख देने पर छोड़ छुट्टी हो जाती है जिसकी मान्यता न्यायालय की आज्ञप्तिवत होता है जबकि सम्पूर्ण भारत मे हिन्दु विधि के अन्तर्गत वैवाहिक संबंध विच्छेद की आज्ञप्ति जरूरी है जो बहुत ही खर्चीली है व समय लेती है, समाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण व प्रथम ईकाई मे ही विषमता कहा तक औचित्यपूर्ण है? यह विचारणीय प्रश्न है।

क्षेत्रीय बिषमताओ का ज्वलंत दृष्टांत यमुना एक्सप्रेसवे है जो जमीन ऊर्जा क्षेत्र में आती है उसका सर्किल रेट अधिक है जबकि उसी जमीन का दूसरा भाग अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में पड़ता है वहां सर्किल रेट बहुत कम रखे गए जिससे पीड़ित किसान आंदोलन के लिए विवश हुए समानता के सिद्धांत के विपरीत है जिसकी प्रत्याभूति संविधान में भी दी गई है फिर भी शासन/प्रशासन अनुचित विभेदीकरण करता है, जोकि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है उत्तर प्रदेश के आदिवासी इलाकों में गरीबी अपने चरमोत्कर्ष पर है जहाॅ नक्सलवाद जैसे संगठन सरकारों को भी चुनौती दे रहे है समस्या का हल लाठियां या गोलियों से नहीं हो सकता, वहाॅ सामाजिक आर्थिक स्थिति कानून से भी नहीं सुधर सकती जब तक कि कानून गरीबोन्मुख नहीं होगा ।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार मे जमीदारी उन्मूलन वह भूमि सुधार कानून के लागू होने के पूर्व उत्तर प्रदेश के एटा जनपद की एक छोटी सी रियासत अवागढ़ के तत्कालीन शासक ने उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त से पूछा कि हमारी जमीन क्यों छीन रहे हो कृषि उत्पादन आयुक्त का उत्तर था हज पुरुष हम आप की जमीन तो ले रहे हैं एवं आप को उचित मुआवजा भी दे रहे हैं आज से ***5*** वर्ष बाद कृषक वर्ग आपको कोई मुआवजा नहीं देगा आज से ***10*** साल के अंदर न केवल आप अपनी जमीन होंगे बल्कि अपना गला कटवा लेंगे इस वार्ता के दिनांक के ठीक ***10*** साल बाद नक्सलवादी आंदोलन शुरू हो गया क्षेत्रीय विषमता विषय में अतः उसके निदान के लिए सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण अपनाते हुए विधियां अलग अलग करना पड़ेगा तभी विशाल से निजात मिल सकती है।भारतीय सामाजिक व्यवस्था व्यवस्था सामंती सामाजिक व्यवस्था की अपरोक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए नए युग में प्रवेश जी दर्ज प्रतीत होती है क्योंकि हमारा राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास

आधुनिक पूजा राज के देसी विकास को सुनिश्चित प्रदान नहीं कर पाया है मध्ययुगीन सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक अवशेषों के दायित्व हमारे संविधान के लोक कल्याण के उद्देश्य पर प्रभावी होने का प्रयास परिलक्षित हो रहा है सदा सामंत वादियों की भाग ***89*** शो को किनारे लगाने का दायित्व निर्वहन करने में सफलता नगर नेगी रही है क्योंकि विरासत हमें इससे समाज विरासत सन हमें इससे समाज मिला है जिसमें उनको मना किया गया है वह सदस्यों से असमानता को मुसीबत आरोपित कर जीवन के एक आवश्यक नियम के रूप में लागू किया जाता रहा है भारतीय समाज में जाति आधारित समाज की स्थिति मजबूत है कि व्यक्ति कितना भी योग्य चुनाव उसकी योग्यता का आकलन उसकी जाति धर्म से किया जाता है जाति का है तो उसे सफलता प्राप्त करने में ज्यादा संघर्ष नहीं करना है बल्कि छोटी.छोटी कार्य कौशल सफलता के पायदान पर पहुंच जाता है या आधुनिक आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भले ही हो उसे हर प्रकार से यथा आर्थिक सामाजिक प्रताड़ना झेलने के बाद ही सफलता ही प्राप्त होती है। सामाजिक विषमता के संदर्भ में प्रख्यात कवि अरुण काम लेने बड़े ही मार्मिक ढंग से शत प्रतिशत सही कहा है

"जो जीवन हम जीते हैं; तुमने काश जिया होता, अंतः स्थल का भावुक कवि, निश्चय बाजाल हुआ होता, प्रतीक्षेपित रोटी का टुकड़ा, तुम थूक.थूक कर देते हो ,पाषाण ह्रदय की पूर्तिमान, तुम नाम खुदा का लेते हो"।

भारत मे आर्थिक / क्षेत्रीय बिषमताओ के कारक:

1.*भूमि स्वामित्व सम्बन्धित बिषमताये**.स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी स्वतंत्रता के बाद प्रथा समाप्त होने पर भी भूमि के स्वामित्व में ज्यादा परिवर्तन नही हो सका है,सीलिंग अधिनियम के लागे होने के बावजूद इस समय देश के ***10% ग्रामीणों के पास कृषि भूमि का लगभग ***56%*** भाग है तथा ***70%*** लोगों के पास केवल 14% भाग है भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद ग्रामीणों के क्षेत्रों में आय के साधन नगण्य है, मजबूरन उन्हें शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन हेतु पलायन करना पड़ता है।

शहरी क्षेत्र मे निजी साम्पत्तिक स्वामित्व की परम्परा.शहरी क्षेत्रों में यातायात सुविधा औद्योगिक स्थानापन्नता के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा व्यापार और पूंजी निवेश शहरों में करना अधिक उपयोग समझते हैं जिससे कि शहरी क्षेत्रों में निजी संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा मिलता है।

उत्तराधिकार कानूनो का प्रचलन. भारत में प्रचलित विरासत की तथा संपत्ति वितरण की श्रंखला विषमताओं को बढ़ा रहीं है किसी निर्धन व्यक्ति की मृत्यु पर उसके वंशजों को उत्तराधिकार स्वरूप उसकी संपत्ति की वजह मृतक द्वारा दिए गए ऋणो का दायित्व मिलता है जबकि धनी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके उच्चधिकारियों को विरासतन संपत्ति मिलती है उत्तराधिकार के कानून के नियमों के कारण भारतीय समाज में निर्धन व धनी वर्ग की उत्पत्ति से क्षेत्रीय विषमताओं के बीच रोपित होते हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण का अभाव एवं बेरोजगारी.भारत ने कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग की बहुतायतता भी है किंतु पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण से भारतीय कौशल्यता कि अनदेखी व अपर्याप्त व्यवसाय प्रशिक्षण को संरक्षण न मिलना, क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाता है पारंपरिक कौशल्यता में रुचि होने के बावजूद व्यक्ति जीवन यापन हेतु अप्रशिक्षित कार्य करने पर मजबूर होता है तथा अपने बच्चों को अन्य व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित एवं पारंपरिक पुश्तैनी व्यवसाय हेतु हतोत्साहित करने पर विवश है क्योंकि कुछ व्यवसाय यथा वकील, डॉक्टर,व्यवसायिक प्रबंधक,इंजीनियर आदि की आए अन्य व्यवसाय में लगे लोगों की तुलना में अत्यधिक होती है इन व्यवसाय में प्रशिक्षण भी अधिक महंगा होने के कारण साधारण ***1*** निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए असंभव

है भारत में बेरोजगारी की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है अधिकांश बेरोजगार समाज के निर्धन वर्ग से ही आते हैं क्योंकि धनाभाव के कारण उन्हें पर्याप्त व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है बामुश्किल स्कूली शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। सरकार द्वारा नौकरियों की समाप्ति, व्यवसायिक निजी करण, नौकरियों को समय पर विज्ञापित न करना, भाई भतीजावाद इत्यादि कारण भी आर्थिक क्षेत्रीय बिषमताओ को बढ़ावा देते हैं।

महंगाई व अप्रत्यक्ष करों की अधिकता. विगत वर्षों में भारत में दोनों प्रत्यक्ष कर आयकर निगम करा दी तथा अप्रत्यक्ष कर उत्पादन कर विकी कर आयात निर्यात कर आदि अप्रत्याशित रूप से जनता पर अधिक रोपित किए गए हैं अप्रत्यक्ष करों का धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग को अधिक भार उठाना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई का दंश निर्धन वर्ग को अधिक झेलना पड़ता है अत्यधिक महंगाई के कारण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही सारी कमाई लग जाती है बची कुची आए कर देने में चली जाती है वर्तमान परिपेक्ष में धनी अधिक धनी एवं निर्धन अधिक निर्धन होता जा रहा है किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए यह स्थिति घातक दुष्परिणाम का घोतक है। कर चोरी, कालाबाजारी, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्मगलिंग आदि श्वेत व्यसन अपराधो की वृद्धि हुई है, सरकार ने भी समय.समय पर काले धन को गैरकानूनी बनाने की अपेक्षा सफेद धन में परिवर्तन के अवसर प्रदान कर देश में आए और संपत्ति के वितरण की असमानता में वृद्धि की है।

वित्तीय संस्थाओ की क्रेडिट पॉलिसी से देश में बैंकिंग एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं जैसे औद्योगिक बैंक, औद्योगिक वित्तीय एवं साख निगम ,राज्य वित्त निगम ,जीवन बीमा निगम, बैंकों का निजीकरण तथा बैको का विलय ने पूंजी पतियों को ही अधिक ऋण दिया है एवं ऋण दायित्व संबंधी नियमों में भी शिथिलता के कारण धनाढ्य वर्ग के लोग ऋण लेकर विदेशों में बस जाते हैं जिसके कारण उनसे ऋण प्राप्ति असंभव हो जाती है इसके विपरीत निर्धन वर्ग को साख नियम के कारण ऋण बमुश्किल बैंकों द्वारा प्राप्त होता है किसी कारणवश बैंक ऋण चुकाने में देरी हो जाती है तो उक्त वर्ग पर नियमों का कठोरता से पालन कर उसे दंडित किया जाता है सरकार द्वारा दोहरी नीति का अपनाएं जाना आर्थिक विषमताओं की खाई को कम करने की अपेक्षा बढ़ावा दिया जाना संभाव्य भविष्य मे घातक दुष्परिणाम ही प्रदर्शित करेगा।

आर्थिक क्षेत्रीय बिषमताओ के कारक

***1.*ऐतिहासिक कारक**:भारतीयो ने सदियों तक क्रमशः मुगलों यूरोपियों आदि की दास्तां जेली है सोने की चिड़िया कहलाने वाले राष्ट्र का लगा था विदेशी अकरांत प्रांतों में भरपूर दोहन किया अंग्रेज उद्योगपति अपनी आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से 2 राज्यों में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में केंद्रित रखते थे प्रमुख रूप से कोलकाता मुंबई और चेन्नई में उन्होंने अपने समस्त नगरों तथा उसके आसपास केंद्रीय करण के कारण उत्पन्न अगर विकसित हो हो गई रोजगार की तलाश में भारतीयों का पलायन बहुतायत में हुआ आर्थिक विषमता मुख का मुख्य घटक घटक का बीजारोपण यहीं से शुरू हुआ।

*2.***भौगोलिक कारक**:भारत मैं प्राकृतिक संसाधनों में पहाड़ियों नदियों व घने जंगलों की अधिकता है जो कि संसाधनों की गतिशीलता को आंशिक रूप से कठिन बना देती है प्रतिकूल जलवायु बाढ़ सूखा आदि भी देश के विभिन्न क्षेत्रों के दी में आर्थिक विकास एवं कृषि की निम्न उत्पादकता एवं अधिकता अविकसित औद्योगिकरण की वजह से देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान समृद्धि हुई है।

***3.*आधारिक संरचना:**मौलिक आधारिक संरचना के अभाव वाले राज निजी निवेश को आकर्षित करने में असफल रहते हैं दूसरी ओर आधारिक संरचना जैसे शक्ति संसाधनों से समृद्ध राज्य बड़ी निवेश योजनाओं को आकर्षित करने में सफल रहते हैं।

***4.*सार्वजनिक निवेश का गिरता स्तर व प्रति व्यक्ति आय मे कमी:**नयी आर्थिक नीति मैं सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी को सीमित करने की उपक्रमों का मार्ग सरकार द्वारा अधिक प्रशस्त करने के कारण सार्वजनिक निवेश में गिरावट आई है इस व्यवस्था का निर्धन व विकासशील राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है प्रति व्यक्ति आय बेरोजगारी अल्प नौकरी आदि के कारण कारकों के कारण प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा अत्यंत निचले स्तर पर पहुंच गया है।

***5.*निर्धनता रेखा के निचले स्तर पर जनसामान्य** :उप्लब्ध आंकड़ों के अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की प्रतिशतता लगभग 8 दशमलव 10% हिमाचल प्रदेश 23.1 प्रतिशत बिहार 45% उत्तर प्रदेश 51% मध्य प्रदेश तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी क्रमश 13.7% और 30.7% है विश्व स्तरीय गणना के हिसाब से भारत में गरीबी 72.9% है।

***6.*प्रतिव्यक्ति कृषि उत्पादन:**भूमि उपजाऊपन के आधार पर कृषि उत्पादन का अनुपात प्रदेशों में भिन्न है यथा पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन अन्य प्रदेशों में काफी कम है साथ ही अत्याधुनिक कृषि उपकरणों की कमी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में दिवास्वप्न मात्र है।

***7.*यातायात एवं संचार:**हिमाचल प्रदेश,जम्मू.कश्मीर आसाम बिहार उड़ीसा आदि प्रदेशों में यातायात संचार बैंक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव तथा पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु में उक्त संस्थाओं की बहुतायत रिता क्षेत्रीय असंतुलन का प्रमुख कारक है जिसके कारण सुविधा युक्त प्रदेशों में पलायन करने से भी अभावग्रस्त प्रदेशों में आर्थिक विकास की रफ्तार थम जाती है।

***8.*औद्योगिकीकरण एवं व्यवसायिक प्रतिस्पर्द्धा:**भारत मे कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होने पर औद्योगिकरण एवं व्यवसाय में उन्नति प्रभावित होती है महाराष्ट्र बंगाल हरियाणा में आए तब उचित तथा बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश राजस्थान आदि प्रदेशों में निम्न स्तर होने से व्यवसाय प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय विषमता 'आंदोलन' में बदल जाती है।

***9.*वित्ताभाव:**भौगोलिक दृष्टि से सम्पन्न प्रदेशों मे उद्योग स्थापना हेतु निवेशक आसानी से मिल जाते हैं किंतु भौगोलिक दृष्टि से जटिल प्रदेशों में पलायनवादिता के कारण मानव संपदा भी नगण्य होने से निवेशक नवीन उद्योग स्थापित करने से कतराते हैं, वित्त अभाव के कारण प्रादेशिक विषमता की खाई बढ़ती ही जाती है जिसका प्रभाव किसी भी क्षेत्र के निर्विघ्नं विकास में प्रमुख वाधा है।

***10.*राजनीतिक दबाव एवं राजनीतिकरण:** राजनीतिक दल निर्वाचन तक लुभावने वादे करते हैं ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहें जीतने के बाद प्रतिद्वंदी दलों से बदला लेने की प्रक्रिया ही अपनाते हैं ना कि चुनाव में जनता से किए वादों को के तथा प्रदेश से दोनों स्थानों पर जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है उसी प्रदेश को कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का हरसंभव लाभ मिलता है अनुचित राजनीतिक दबाव और राजनीतिकरण

क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को कम करने के बजाय बढ़ावा मिलने से आर्थिक उन्नयन में मुख्य बाधा के रूप में परिलक्षित होते हैं।

परिणामिक प्रभाव व प्रतिक्रिया

भारत गांवों में बसता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के बिना भारत के शहरी क्षेत्र में विकास अधूरा ही रहेगा वैश्विक मंदी के मारे प्रबंधक इंजीनियर कब तक मशीनों को भोजन के लिए किसानों की शरण ही लेनी होगी आंध्रा महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण भी अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य तक नहीं मिल रहा है सूखा बाढ़ का दंश झेल रहे दलित. पैंथर नामक कवि ने एक किसान की जीवन कथा में ठीक ही कहा है :-

"दुनिया का सर्वोच्च उठाएं झुका हुआ निधन पर आयोजित आमुख पर जिसके ढूंढा बोतल पर निष्काम कर्म लगा रहा उगाता जन.जन को उसमें बिना हिमालय पसंद नहीं है उसको आशुतोष अधिपति होकर झोपड़ियों में बसता है वर्मा शिव हुआ कदाचित तांडव भी कर सकता है"। (अनुदित अंश)

अमेरिका के पश्चिम की अर्थव्यवस्था को मंदी के संकट ने जिस में अभिनय से अधिक लोग विष्ठा में प्रबंधन के लालच में भयानक आग संकट उत्पन्न किया जिसके को प्रभावों से भारत भी अछूता नहीं रह पाया भारत पर इसका असर 2008 के चतुर्थांश में ही प्रदूषित हो चुका था तथा मांग के बाजारों की गिरावट बढ़ गई मुद्रास्फीति बढ़ गई थी से अछूता नहीं रहा होने को आए अभी उसके परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे हैं मंदी के इस ग्रुप से बचने के लिए बड़े लोगों पर कराधान व विदेशों में जमा राजनीतिज्ञों के खातों के काले धन को भारत लाकर व्यापारियों को संतुलित किया जा सकता है नोटबंदी या काले धन को वापस लाने की घोषणा को इसका विकल्प नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए धरातल पर भी अति आवश्यक है क्षेत्रीय विषमता जातिगत दूरियों को भी बढ़ाते हैं असंभव जातिगत दूरियां घटाने के लिए योग्यता का मानक निर्धारण करना ही पड़ेगा योग्यता को उसका उचित स्थान देना पड़ेगा विजय कुमार जाति पाति पर प्रभाव प्रहार करते हुए स्पष्ट कीजिए हमें विरासत में हिंदू समाज में लाएं और घमंड पर रोक लगी है जिसमें जीवन का आधार असमानता को मान लिया है रोमन भाषा का विकास हो सकता है हो सकता है हिंदुस्तान में व्यक्ति एक जाति विशेष में पैदा होता है उसी में मरता है उसकी योग्यताएं उसी के साथ दफन कर दी जाती है आज के युग में एक सीमित हद तक मान सम्मान पा सकते हैं पर योग्यता का कोई मूल्य नहीं रह गया है शब्दों में यहां सामानों में समानता और असमानता का व्यवहार किया जाता है वही अन्याय होता है"।

उपसंहार

संक्षेप मे उपरोक्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष निकालना प्रासंगिक होगा कि भारत में क्षेत्रीय विषमताओं की जड़ें इतनी गहरी जमी है कि उन्हें समूल नष्ट नहीं किया जा सकता जिनका कारण यहां की रात जातिवादी व्यवस्था है जो असमानता पर आधारित है योगिता पृष्ठभूमि में चली जाती है मंदी का प्रभाव सर्वाधिक ग्राम अर्थव्यवस्था पर पड़ा है जिन्हें अधिक लागत पर सच में लेकर उत्पाद कम कीमत पर बेचना पड़ता है बैंक के कर्जे की अदायगी न होने पर कुंठित कृषक महाराष्ट्र गुजरात आदि राज्यों में आत्महत्या कर रहे हैं उनकी दयनीय दशा के लिए अधिक मंदी को ही जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है सरकार द्वारा जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं बह पारदर्शी होनी चाहिए ,पारदर्शिता के अभाव में ही बिभिन्न क्षेत्रीय किसान आंदोलन की पराकाष्ठा इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध दार्शनिक लेनिन के कथन "हम व्वैयक्तिक जैसी कोई चीज नहीं मानते हमारे लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की प्रत्येक बात जन विधि का चरित्र रखती है न कि व्यैक्तिक विधि", से

(MIJ) 2015, Vol No 1, Jan-Dec **e-ISSN: 2454-924X; p-ISSN: 2454-8103**

मै पूर्णत: सहमत हूं क्योंकि "जिसने चखी न दुख की रोटी,मध्यरात्रि तक नहीं जगा, रोकर की न प्रतीक्षा कल की, बन न सके जगदीश सगा"।

सन्दर्भ सूची

- जयजय राम उपाध्याय : भारत का संविधान
- जे एन पाण्डेय :भारत का संविधान
- क्राइम इन इण्डिया,2004,एनसीआरबी,गृह मन्त्रालय भारत सरकार
- मिनिमम बेजेज एक्ट,1948
- फैक्टरीज एक्ट,1954
- वोन्डेड लेबर सिस्टम (एबोलिशन)एक्ट,1976
- भारतीय दण्ड संहिता

REFERENCES

- Jaijai Ram Upadhyay: Constitution of India
- J N Pandey: Constitution of India
- Crime in India, 2004, NCRB, Home Ministry, Govt of India
- Minimum Wages Act, 1948
- Factories Act, 1954
- Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
- Indian Penal Code